DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । बुधवार, 18 जनवरी 2023

असेंबली में उठा झुग्गियों को डिमॉलिशन नोटिस देने का मुद्दा

■ **विस, नई दिल्ली :** पिछले कुछ महीनों में डीडीए समेत कई अन्य एजेंसियां दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में एनक्रोचमेंट हटाने के नाम पर झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए नोटिस थमा रही है। आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ कुछ जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी कर चुकी है। मंगलवार को विधानसभा में भी यह मुद्दा उठा और कई विधायकों ने इस पर चिंता जताई।

आप विधायक सहीराम ने विशेष चर्चा की शुरुआत की, जिसमें सत्ता पक्ष के विधायक राजेश गुप्ता, नरेश यादव, अजय दत्त, रोहित महरौलिया, अखिलेश पति त्रिपाठी, भूपेंद्र सिंह जून, शिवचरण गोयल और आतिशी ने भी हिस्सा लिया। इन सभी विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्र में झुग्गी बस्तियों को हटाने के लिए नोटिस दिए जाने का दावा करते हुए डीडीए व अन्य सरकारी विभागों की मंशा पर सवाल उठाए। इसे लेकर बीजेपी और एलजी को भी घेरा और चेतावनी दी कि अगर एक भी झुग्गी पर बुलडोजर चलाने का प्रयास किया गया, तो AAP सड़क पर उतरकर उसे रोकेगी। आप विधायकों ने बीजेपी पर चुनाव से पहले लोगों से झूठ बोलने और झुग्गी की जगह पर ही मकान बनाकर देने का झूठा वादा करने का आरोप लगाया। इसके बावजूद एमसीडी चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना, तो अब दिल्ली के झुग्गीवासियों से बदला लिया जा रहा है।

डीडीए ने इन्हें हैंडओवर करने का लिया फैसला, शुरू की कवायद

अब नगर निगम करेगा द्वारका में सड़कों और स्ट्रीट लाइटों की मेंटिनेंस का काम

■ विशेष संवाददाता, द्वारका

द्वारका के विकास के लिए कई एजेंसियां काम में लगी हैं। इस वजह से विभागों और लोगों को भी कई परेशानियां आती हैं। अब यह परेशानियां दूर होने वाली हैं। अब यहां की सड़कें, स्ट्रीट लाइटें आदि की जिम्मेदारी डीडीए ने नगर निगम के हवाले करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए डीडीए और निगम के अधिकारी मिलकर सर्वे में जुट गए हैं। इस सर्वे में यह पता लगाया जा रहा है कि कहां-कहां काम चल रहे हैं और कहां पर विकास कार्यों की जरूरत है। इसके बाद एक एस्टीमेट बनाकर डीडीए यहां की सड़कों और स्ट्रीट लाइटों का जिम्मा निगम को सौंप देगा। इसमें अभी कुछ महीनों का समय लग सकता है।

अभी तक 6, 9, 12, 20 और 30 मीटर की सड़कों को निगम के अंतर्गत करने को लेकर फैसला लिया गया था। लेकिन कुछ दिन पहले हुई बैठक में 45 से 60 मीटर चौड़ी सड़कों को भी निगम को सौंपने का फैसला डीडीए ने लिया है। सर्वे में सड़क के साथ बिजली के खंबे भी निगम के हवाले किए जाएंगे। इनके रखरखाव से लेकर नई स्ट्रीट लाइटें लगाने का काम निगम ही करेगा। साथ ही सड़कों पर फुटपाथ और सेंट्रल वर्ज पर लगाए गए पौधे की देखरेख भी निगम ही करेगा। पेड़ों की छंटाई और नए पौधे लगाने की जिम्मेदारी भी नगम की होगी।

फिलहाल निगम और डीडीए के अधिकारी सर्वे के काम में लगे हैं

क्यों महसूस हुई जरूरत

दरअसल द्वारका में विकास कार्यों के लिए कई विभाग काम करते हैं। इलाके में कई सड़कें, स्ट्रीट लाइटें निगम के अंतर्गत पहले से हैं। ऐसे में कई बार देखा गया कि द्वारका के लोगों को यह पता नहीं चलता कि कौन सी सड़क निगम के अंतर्गत है और कौन सी डीडीए के अंतर्गत। लोगों को शिकायत करने में भी परेशानी होती थी। एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता था। साथ ही डीडीए अधिकारियों के बार-बार तबादले का असर विकास कार्यों पर पड़ता था। ऐसे में इस समस्या के स्थाई समाधान की दिशा में पहल की गई।

दी गई हिदायत

डीडीए की तरफ से द्वारका जोन के सभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों को हिदायत दी गई है कि द्वारका में डीडीए कई सड़कें एमसीडी को हैंडओवर कर रहा है। इसके लिए फिजिकल सर्वे हो रहा है और डिफिशिएंसी एस्टीमेट तैयार कर रही हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों को कहा गया है कि मैन्युअल इंस्पेक्शन के बाद होने वाले डिफिशिएंसी एस्टीमेट के बाद उक्त साइट पर कोई काम न किया जाए।

हेल्थ कैंप आयोजित

■ **उत्तराखंडी** लोक संस्कृति के पर्व उत्तरैणी पर शनिवार को उत्तराखंडी उत्तरायणी समिति ने द्वारका सेक्टर 14 के डीडीए ग्राउंड में रंगारंग कार्यक्रम किया। समिति की संयुक्त सचिव प्रीति कोटनाला ने बताया कि वेंकटेश्वर हॉस्पिटल की ओर से निशुल्क स्वास्थ्य जांच की गई। मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद रावत, समिति के अध्यक्ष टी पी जोशी, चेयरमैन प्रेम सिंह रावत मौजूद थे। गायक मंगलेश डंगवाल, मनराल ग्रुप, प्रकाश काला, संगीता ढौंडियाल और खुशी जोशी ने प्रस्तुति दी।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPE नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । बुधवार, 18 जनवरी 2023 DATED----------

एडब्ल्यूसी-2023 के सेंसस में 15 प्रजातियों के 219 पक्षी यहां देखे गए हैं

संजय झील में इस बार आए ज्यादा परिंदे

विस, नई दिल्ली : सर्दी के मौसम के बीच उत्तरी एशिया से आने वाले कुछ विदेशी परिंदों का आना शुरू हो गया है। संजय झील का हेबिटेट धीरे-धीरे खराब होने के बावजूद इस बार राजधानी की इस झील को परिंदों ने पसंद किया है। एडब्ल्यूसी (एशियन वॉटरबर्ड सेंसस)-2023 के अनुसार इस झील में न सिर्फ पिछले साल की तुलना में पक्षियों की कुछ अधिक प्रजातियां पाईं गईं। इनकी संख्या में भी इजाफा हुआ है।

एशिया और ऑस्ट्रेलिया में होने वाला यह सेंसस 7 जनवरी से शुरू हुआ है। एडब्ल्यूसी के दिल्ली स्टेट को-ऑर्डिनेटर और इकोलॉजिस्ट टी. के. राय ने बताया कि जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम में बदलाव हुआ है। इस साल नवंबर-दिसंबर की सर्दियां छठी सबसे गर्म सर्दियां हैं। साथ ही सर्दियां देरी से भी शुरू हुई हैं। इसी वजह से उत्तर भारत में विदेशों से लंबी यात्रा करके आने वाले पक्षी देर से आना शुरू हुए हैं। यह परिंदे मध्य एशिया, उत्तरी एशिया(रूस और साइबेरिया) से आते हैं।

कितने पक्षी आए

साल	पक्षी	प्रजाति
2022	132	13
2023	219	15

(इनमें से 4 प्रजातियां विदेशी हैं। इनमें ग्रेट कारमोरेंट 3, टेमिंक्स स्टिंट 42, बार्न स्वालो 19 और ग्रे वैगटेल शामिल)

राय ने बताया कि संजय झील 17 एकड़ में फैली है। इसकी देखरेख डीडीए करता है। पहले यह झील काफी बड़ी थी। बाद में इसके कुछ हिस्से को डीडीए ने विकसित किया। बाकी झील सूख चुकी है। यह झील हजारों पक्षियों की पसंदीदा हुआ करती थी, लेकिन अब झील में मनोरंजक गतिविधियां बढ़ गई हैं। झील के आसपास विकास कार्यों की वजह से यहां कंक्रीट का जाल बढ़ गया है। इसलिए यहां की जैव विविधता पर बुरा असर पड़ा है। अब कभी कभार ही यहां पर विदेशी पक्षी आते हैं, लेकिन यह मानवीय डिस्टरबेंस जैसे बोटिंग आदि की वजह से लंबे समय तक यहां नहीं ठहरते। साथ ही इस झील में आसपास की कॉलोनियों का सीवर भी आता है, जिसकी वजह से झील प्रदूषित हो रही है। एडब्ल्यूसी-2023 में दिल्ली यूनिवर्सिटी, कुमाऊ यूनिवर्सिटी, दिल्ली वेटलैंड अथॉरिटी और दिल्ली के पक्षी प्रेमियों ने भी हिस्सा लिया।

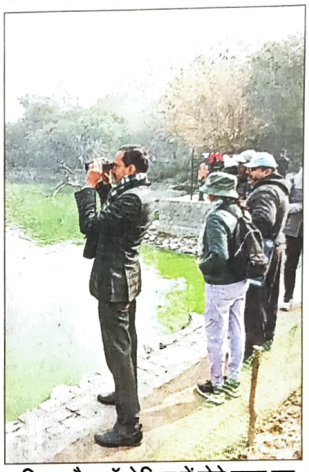

एशिया और ऑस्ट्रेलिया में होने वाला यह सेंसस 7 जनवरी से शुरू हुआ है

90% सरकारी स्कूलों में टीचरों की कमी : बीजेपी

प्रस, नई दिल्ली : 'दिल्ली सरकार के 90 प्रतिशत स्कूलों में टीचर्स की कमी है। बेहतर शिक्षा के लिए दिल्ली सरकार पहले छात्र-टीचर्स अनुपात को बेहतर बनाए। इसके बाद फिनलैंड में ट्रेनिंग की बात करे।' यह कहना है कि दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर का।

कपूर के अनुसार, डीडीए ने दिल्ली सरकार को स्कूल बनाने के लिए 13 जगहों पर जमीन उपलब्ध कराए हैं। स्कूल निर्माण के लिए जमीनें दिल्ली सरकार को नवोदय स्कूल फाउंडेशन को आवंटित करना है। लेकिन, सालों से दिल्ली सरकार ने जमीनें आवंटित नहीं की हैं। न तो जमीन आवंटित किया जा रहा है और न ही स्कूल निर्माण शुरू हो पा रहा है। आम आदमी पार्टी विधायक अतिशी शिक्षा को लेकर लंबी-चौड़ी बातें तो करती हैं, लेकिन उनकी सरकार ने शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कुछ खास नहीं किया है। फिनलैंड में कुछ शिक्षकों को ट्रेनिंग कराने से दिल्ली की शिक्षा में क्रांति नहीं आ सकती। बेहतर शिक्षा के लिए जरूरी है स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात को बनाना। दिल्ली सरकार के 90 प्रतिशत स्कूलों में टीचर्स कम हैं। कई स्कूलों में तो प्रिंसिपल ही नहीं हैं। फिनलैंड में टीचरों को ट्रेनिंग से ज्यादा जरूरी स्कूलों में स्टाफ की संख्या पर्याप्त बनाए रखना है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWS दैनिक जागरण नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2023 ---------DATED----------

झुग्गीवासियों के साथ है आप सरकार : राय

राब्यू, नई दिल्ली: दिल्ली में झुग्गियां हटाने के विरोध में मंगलवार को विधानसभा में सत्तापक्ष ने केंद्र सरकार और डीडीए पर हमला बोला। आप के विधायकों ने भाजपा पर एमसीडी चुनाव में हार के बाद झुग्गियां हटाने की साजिश रचने का आरोप लगाया।

गोपाल राय ●

दिल्ली में झुग्गी हटाने के नोटिस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर सदन में चर्चा के दौरान विकास मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार झुग्गीवासियों के साथ खड़ी है। सदन में विधायक नरेश यादव और अजय दत्त ने अपने यहां झुग्गी हटाए जाने के आदेश देने की बात कही। इस पर राय ने कहा कि हम आजादी के 75 साल बाद भी भारत के बेटे-बेटियों को इतना लायक क्यों नहीं बना सके कि वे झुग्गी-झोपड़ियों में न रहें। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में जब दिल्ली में आप की सरकार बनी थी, तो हमारा मानना था कि अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, लेकिन जब तक पुनर्वास की पुख्ता व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक कोई डेमोलेशन नहीं होना चाहिए। आप विधायक आतिशी ने कहा कालकाजी में झुग्गियों के विस्थापन का नोटिस बड़ा गंभीर मुद्दा है। नगर निगम के चुनाव खत्म होते ही भाजपा ने शहर के कई हिस्सों में झुग्गियां गिराने के लिए नोटिस जारी करनी शुरू कर दीं। लेकिन, हमारी सरकार किसी भी सूरत में दिल्ली की झुग्गियों को नहीं उजड़ने देगी।

विधायकों ने सदन में रखीं अपने क्षेत्र की समस्याएं

- ड्रग्स के कारोबार, जलसंकट, टूटी सड़क व पेंशन का मुद्दा उठाया
- विस अध्यक्ष ने कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को भेजीं समस्याएं

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: विधानसभा सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को विशेष उल्लेख (नियम संख्या 280) के तहत विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं भी रखीं। विधायकों द्वारा उठाई गई सभी समस्याओं को विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को अग्रसारित कर दिया।

बिजवासन से आप विधायक भूपेंद्र सिंह जून ने अपने क्षेत्र में ड्रग्स के कारोबार का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इसे लेकर पुलिस को पत्र भी लिखा गया और लोकेशन भी दी गई। उपराज्यपाल और पुलिस आयुक्त को भी पत्र भेजा गया, लेकिन आज तक किसी भी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

गांधी नगर से भाजपा विधायक अनिल वाजपेयी ने दोहराया कि उनके क्षेत्र से एसडीएम कार्यालय नंद नगरी शिफ्ट कर दिया गया है जिसके कारण तीन विधानसभा क्षेत्र के लोग प्रभावित हो रहे हैं। एसडीएम कार्यालय को दुबारा गांधी नगर लाया जाए। अगर महीने भर में इसे वापस शिफ्ट नहीं किया गया तो वह धरने पर बैठेंगे।

भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि रोहिणी विधानसभा के सेक्टर-18, 19 और आसपास के क्षेत्र में लगभग एक लाख से अधिक की आबादी है, लेकिन वहां एक भी सरकारी स्कूल नहीं था। काफी प्रयास के बाद एक सरकारी स्कूल भवन का निर्माण कराया गया, लेकिन इसके बावजूद उसमें रोहिणी के सेक्टर-18 19 एवं आसपास के क्षेत्रों में रह रहे लोगों के बच्चों को दाखिला नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि यह स्कूली शिक्षा के अधिनियमों के विपरीत है और संविधान के शिक्षा के अधिकार का भी उल्लंघन है। शिक्षा नियमों के अनुसार बच्चों को उनके घर के नजदीक ही स्कूली शिक्षा मिलनी चाहिए।

आप विधायक नरेश यादव ने महरौली में आर्कियोलाजिकल पार्क के नाम पर डीडीए द्वारा झुग्गियां तोड़ने, राजेंद्र पाल गौतम ने सीमापुरी में फुटपाथ पर अतिक्रमण, गोकुलपुरी से आप विधायक सुरेंद्र कुमार ने अपने विधानसभा क्षेत्र में जलसंकट और प्रीति तोमर ने त्रिनगर के 20 में से 13 बस क्यू शेल्टरों के टूटे होने का मुददा उठाया। वहीं, नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्लीवासियों को राशन न मिलने का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री की ओर से मिलने वाला राशन भी एफसीआइ के गोदामों से नहीं उठाया जा रहा और दो माह से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाला राशन भी नहीं उठाया। इसके अलावा राशन दुकानदारों को छह माह से कमीशन भी नहीं मिला है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------- DATED---------- THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
WEDNESDAY, JANUARY 18, 2023

If bulldozers used in slums, AAP will come in way: Rai

Abhinav.Rajput@timesgroup.com

New Delhi: A row erupted on Tuesday over the notices to villagers in Tughlaqabad to vacate the area, with AAP MLAs accusing BJP of "conspiring" to demolish slums after its loss in the MCD polls and the saffron party saying there were court orders for their removal.

"There are skyscrapers in Delhi, but people who manage the lives of those residing there themselves live in inhuman conditions in jhuggis even after 75 years of independence," said AAP minister Gopal Rai during a debate in the Assembly over a calling attention motion on 'demolition notices received by residents of Tughlaqabad village'.

Rai said the government will take up the issue and, if needed, won't hesitate to take to the streets to stop demolition of slums. "If you have bulldozers, AAP has the chest to stand in front (of them)," he said, adding that unless rehabilitation is carried out, no new demolition can take place.

TOI had earlier reported that ASI served over 1,000 notices during its anti-encroachment drive to clear squatters in the protected Tughlaqabad Fort area. The encroachers had been asked to vacate the space within 15 days or face demolition.

Initiating discussion on the motion, Tughlaqabad MLA Sahiram demanded registration of FIRs against officers who allowed development of the colony in his constituency.

GOPAL RAI SAYS

There are skyscrapers in Delhi, but people who manage the lives of those residing there themselves live in inhuman conditions in jhuggis even after 75 years of independence

"What were the officers doing when the colony was developing? Nearly 10,000 houses have been constructed there. There are 20,000 residents with voter ID cards and they have been given 15 days to vacate," Sahiram said, urging the Speaker and CM to take up the issue with the Centre and stop the demolition.

Kalkaji MLA Atishi said in several parts of the city, notices for demolition of slums started being issued a few weeks after BJP lost the MCD polls. "It is a pre-planned conspiracy of BJP to clear slums in Delhi. I want to tell the BJP, LG and DDA that no matter how many notices they issue, no bulldozers will be allowed by the Kejriwal government and AAP," she added.

AAP MLA from Mehrauli Naresh Yadav said people in his constituency are "scared" because of notices sent to them over an upcoming archaeological park. "The notices should be withdrawn. I appeal to the LG not to work against the people of Delhi," he said.

Leader of the Opposition RS Bidhuri accused AAP MLAs of lying in the Assembly without presenting a complete picture of the issue and alleged the Kejriwal government wanted slums to exist for "political reasons". "There is a court order regarding Tughlaqabad village. If AAP MLAs are so concerned, they should ask the CM to withdraw the order surrendering the land to ASI," he said.

Responding to Atishi's claim that DDA had served eviction notices to residents of Subhash camp, which is under Bidhuri's constituency Badarpur, he said the camp was settled on pond land and was to be removed in compliance with an SC order.

BJP MLAs don black to protest AAP 'corruption'

Abhinav.Rajput
@timesgroup.com

ANI

BJP legislators protest outside Delhi Assembly on Tuesday

New Delhi: Dressed in black with black turbans on their heads, the BJP legislators protested in Delhi Assembly against the alleged corruption and swindles involving the AAP government. "Whether it is the purchase of buses, whether it is the Rs 60,000 crore corruption in Delhi Jal Board, whether it is the excise policy, the Kejriwal government is completely embroiled in corruption," declared BJP MLA Ajay Mahawar in the assembly.

Mahawar said, "This government won votes in the name of Lokpal, but is completely embroiled in corruption. Corruption by several ministers have come to light. A minister is in jail for several months and the chief minister is trying to shield him." These allegations led to an uproar in the House.

The Speaker, Ram Niwas Goel, suspended five BJP MLAs — Ajay Mahawar, Jitendra Mahajan, OP Sharma, Abhay Verma and Anil Bajpai — for the day after they protested against AAP MLA Atishi's calling attention motion on the alleged "interference" of lieutenant governor VK Saxena in the matter related to sending primary teachers in Finland for training. The quartet was marshalled out, while two others — Vijender Gupta and Ramvir Singh Bidhuri — staged a walkout from the House. Later, the BJP MLAs sat on dharna on the assembly premises.

Speaking in the assembly, leader of the Opposition Bidhuri later said that the BJP MLAs should be allowed to discuss issues of public interest, such as the ration distribution system and corruption, but weren't being given such opportunities. "Investigating agencies are probing several cases, including excise policy and purchase of DTC buses. The discrepancies in water bill collection also warrants a short discussion. But we are allowed none of this," said Bidhuri.

Bidhuri also claimed that the rationing system had been brought to a standstill. "1.9 lakh quintals of ration grains are in the godown of the government of India. Delhi government has to lift them and give them to migrant workers. The Centre has sent several reminders on this," he said. "But why is Delhi government unable to lift it for three months? What can be a bigger failure for the food and civil supplies department?"

Gupta added, "In my constituency, there are around one lakh people, many of them economically weak. We have been trying for years to build a school for which land was allotted by DDA and a school readied by 2022 at a cost of Rs 45 crore. But Delhi government has taken an arbitrary decision and made it into a School of Specialised Excellence. Bright students from across Delhi can study there, but not the local children."

Gupta said that he does not have a problem with a specialised institution, but it was achieved by removing a regular school. "You run classes in shifts, we will not mind — one shift for regular students of classes I to XII, another for the bright students."

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

the pioneer
NEW DELHI | WEDNESDAY | JANUARY 18, 2023

BJP conspiring for demolition of slums, says AAP

Court ordered removal of Tughlaqabad village slums, retorts BJP

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

The AAP on Tuesday alleged that the BJP is conspiring for demolition of slums in the city after its defeat in the MCD polls. Development Minister Gopal Rai asserted in the Assembly that the Kejriwal Government stands with the slum dwellers.

Rai said it was a clear view of the AAP Government that unless rehabilitation is carried out, no new demolition can take place.

Hitting back, Leader of Opposition Ramvir Singh Bidhuri charged that the AAP MLAs "lied" in the Assembly without presenting complete picture of the issue. He said there were court orders for removal of slums in Tughlaqabad village and Mehrauli area.

Rai, participating in a debate in the House over a calling attention motion on "demolition notices received by residents of Tughlaqabad village", said the Aam Aadmi Party (AAP) government will take up the issue and it will not hesitate to take to streets to stop demolition of slums if need be.

"We will stop it. The government stands with the slum dwellers. It was our view even in 2015 when the AAP formed government in Delhi that there should be no encroachment but no slums should be removed unless people living there are rehabilitated," he told the Assembly. Initiating discussion on the motion, Tughlaqabad MLA Sahiram demanded registration of FIRs against officers who allowed development of the affected colony in his constituency.

"What were the officers doing when the colony was developing? Around 10,000 houses have been constructed there. There are 20,000 residents having voter ID cards and they have been given 15 days' time to vacate," Sahiram said urging the Speaker and Chief Minister Arvind Kejriwal to take up the issue with the Centre to stop the demolition.

Several other AAP MLAs complained of notices served on residents of slums under their constituencies by different agencies.

Kalkaji MLA Atishi said the notices started being issued a few weeks after the BJP lost the Municipal Corporation of Delhi (MCD) polls, for demolition of slums in several parts of the city.

"It is a pre-planned conspiracy of the BJP to clear slums in Delhi. I want to tell the BJP, LG and DDA no matter how many notices they issue, no bulldozers will be allowed by the Kejriwal government and the AAP," she asserted.

She claimed that the Delhi Development Authority (DDA) has served eviction notices on residents of even Subhash Camp slum under Bidhuri's constituency Badarpur.

Bidhuri, however, said the Subhash Camp in his constituency was settled on a pond land and it was to be removed in compliance of a Supreme Court order

पंजाब केसरी DELHI · 18 जनवरी, 2023 ▶ बुधवार

झुग्गीवासियों के साथ खड़ी है केजरीवाल सरकार: गोपाल राय

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली में झुग्गियां हटाने के विरोध में मंगलवार को विधानसभा में सत्तापक्ष ने केन्द्र की भाजपा सरकार सहित डीडीए पर जोरदार हमला बोला। आप विधायकों ने भाजपा पर एमसीडी चुनाव में हार के बाद झुग्गियां हटाने की साजिश रचने का आरोप लगाया। तुगलकाबाद गांव के निवासियों को झुग्गी हटाने के नोटिस पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर सदन में चर्चा के दौरान दिल्ली के विकास मंत्री गोपाल राय ने कहा कि केजरीवाल सरकार झुग्गीवासियों के साथ खड़ी है। इस दौरान सदन में आप विधायक काफी रोष में दिखे। सदन में विधायक नरेश यादव व अजय दत्त ने अपने यहां झुग्गी हटाये जाने के आदेश देने की बात कही जिस पर गोपाल राय ने कहा कि हम आजादी के 75 साल बाद भी भारत के बेटे-बेटियों को इतना लायक क्यों नहीं बना सके कि वे झुग्गी-झौंपडियों

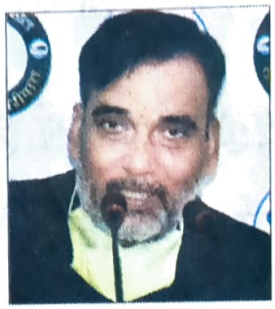

में ना रहें। उन्होंने कहा कि जब 2015 में केजरीवाल सरकार बनी थी तो हमारा मानना था कि अतिक्रमण नहीं होना चाहिए लेकिन जब तक पुनर्वास की व्यवस्था नहीं होती तब तक कोई डेमोलेशन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप सरकार इस मुद्दे को उठाएगी और जरूरत पड़ने पर झुग्गियों को गिराने से रोकने के लिए सड़कों पर उतरने से नहीं हिचकेगी। वहीं आप विधायक आतिशी ने कहा कालकाजी में झुग्गियों के विस्थापन का नोटिस बड़ा गंभीर मुद्दा है। जैसे ही दिल्ली में नगर निगम के चुनाव खत्म हुए भाजपा ने गरीबों को हटाने की कोशिश शुरू कर दी। एमसीडी चुनाव हारने के कुछ हफ्ते बाद ही भाजपा द्वारा शहर के कई हिस्सों में झुग्गियां गिराने के लिए नोटिस जारी किए जाने शुरू हो गए थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसी भी सूरत में दिल्ली की झुग्गियों को नहीं उजडने देगी। आप विधायक रोहित महरौलिया ने कहा कि दिल्ली में 50-50 साल पुरानी झुग्गियां हटाने का मुद्दा अपने आप में महत्वपूर्ण व गंभीर है। मुख्यमंत्री ने जहां झुग्गी वहीं मकान के आदेश जारी किये हैं। डीडीए जान बूझकर झुग्गियां हटा रहा है। उन्होंने विधासभा अध्यक्ष को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा जानबूझकर दिल्ली के लोगों से बदला ले रही है लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे।

अमर उजाला

भाजपा ने शैक्षिक सुधार पर बहस की चुनौती दी

नई दिल्ली। आप विधायक आतिशी को राजनीतिक आकाओं से पूछना चाहिए कि डीडीए ने जब दिल्ली सरकार को 13 स्कूलों के लिए जमीन आवंटित की तो निर्माण कार्य क्यों नहीं हुआ। जवाहर नवोदय स्कूल समिति को वह जमीन क्यों नहीं दी गई। इस बाबत प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने आतिशी को शैक्षिक सुधारों पर खुली बहस की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि आप नेताओं को शिक्षा में सुधार नहीं करना है, लेकिन बड़ी-बड़ी बातें जरूर करनी है। आतिशी से पूछना चाहता हूं कि नवोदय या केवी जैसे अच्छे केंद्र सरकार के स्कूलों के कितने शिक्षकों के पास विदेशी प्रशिक्षित शिक्षक हैं। ब्यूरो

आतिशी को भाजपा प्रवक्ता ने दी खुली बहस की चुनौती

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने विधायक आतिशी को दिल्ली में शैक्षिक सुधारों पर खुली बहस की चुनौती दी है। उन्होंने आप विधायक से कहा है कि वह बताएं कि डीडीए ने स्कूलों के लिए जो 13 टुकड़े जमीन दिल्ली सरकार को अवंटित की, वह क्यों वर्षों से अनुपयोगी पड़ी है। वे बोले कि पिछले कुछ दिनों से हमने आप नेताओं को फिनलैंड में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर बहुत कुछ बोलते हुए देखा है, लेकिन मैं आप नेताओं से पूछना चाहता हूं कि फिनलैंड में कुछ शिक्षकों को भेजने का क्या फायदा है, जब दिल्ली सरकार के 90 फीसद स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक व प्रिंसिपल नही हैं और न ही स्कूलों में विज्ञान या कॉमर्स पढ़ाया जाता है। कहा कि मैं आतिशी से पूछना चाहता हूं कि नवोदय स्कूल या केंद्रीय विद्यालय जैसे अच्छे केंद्र सरकार के स्कूलों के कितने शिक्षकों के पास विदेशी प्रशिक्षित शिक्षक हैं या फिर नामी निजी स्कूलों के कितने शिक्षक विदेश में ट्रेंड होकर आए हैं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- अमर उजाला ----------DATED नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2023

पुनर्वास से पहले दिल्ली में नहीं टूटेगी कोई झुग्गी : गोपाल

नई दिल्ली। मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को कहा कि पुनर्वास से पहले किसी भी झुग्गी को टूटने नहीं दिया जाएगा। यदि जरूरत पड़ी तो आम आदमी पार्टी सदन से सड़क तक इसका विरोध करेगी। विधानसभा में दक्षिणी दिल्ली के झुग्गियों को खाली करने के लिए भेजे गए नोटिस पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी तो फैसला लिया गया था कि कोई नया अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। पुरानी झुग्गियों को पुनर्वास से पहले तोड़ा नहीं जाएगा। सरकार आज भी अपने निर्णय पर कायम है।

वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि निगम चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने कुछ फ्लैट दिखाकर कहा था कि जहां झुग्गी वहीं मकान दिया जाएगा। अब चुनाव खत्म होते ही हजारों झुग्गियों को तोड़ने के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। जरूरत पड़ी तो सदन से सड़क से विरोध प्रदर्शन करेंगे। एलजी अधिकारियों पर दबाव बनाकर इन्हें तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री, उप राज्यपाल और डीडीए इन्हें तोड़ने से पहले पुनर्वास का काम करें।

कई साल से रह रहे हैं लोग

सदन में चर्चा के दौरान विधायक सही राम, अजय दत्त, नरेश यादव ने कहा कि ये झुग्गियां 30-40 साल पुरानी हैं। इनमें लंबे समय से लोग रह रहे हैं, इन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। सही राम ने कहा कि तुगलकाबाद क्षेत्र में जब यह कॉलोनी बन रही थी तो अधिकारी कहां थे। क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यहां 20 हजार से ज्यादा वोट हैं। मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि के केंद्र सरकार को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप करवाएं।

राष्ट्रीय सहारा

सरकार खाली प्लाटों पर नहीं बना रही स्कूल : कपूर

नई दिल्ली (एसएनबी)। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने आप नेताओं से सवाल किया है कि दिल्ली सरकार को 13 स्कूल प्लॉट आवंटित होने के बाद स्कूलों का निर्माण क्यों नहीं कराया जा रहा है। उनका कहना है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने दिल्ली सरकार को 13 स्कूल प्लॉट आवंटित किए है, लेकिन दिल्ली सरकार उन स्कूल प्लॉटों का कब्जा अभी तक जवाहर नवोदय स्कूल समिति को नहीं दिया है। उनका तर्क है कि आप के विधायकों को यह सवाल अपने प्रमुख अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहिए। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि वह इस मुद्दे पर केजरीवाल के विधायकों ने खुली बहस को तैयार हैं।

डीडीए ने केजरीवाल सरकार को दे रखे हैं 13 स्कूल प्लॉट

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि यह 13 स्कूल प्लॉट काफी समय से दिल्ली सरकार के कब्जे में हैं। दरअसल राजधानी में बने सभी नवोदय विद्यालयों का निर्माण नवोदय स्कूल फाउंडेशन ने किया है। उन्होंने कहा कि आप की विधायक आतिशी अक्सर डीडीए पर आरोप लगाती रहती है कि दिल्ली सरकार को स्कूल बनाने के लिए प्लॉट नहीं दे रही है। उनका यह आरोप बेबुनियाद है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया है कि नवोदय स्कूल एवं केंद्रीय विद्यालय जैसे अच्छे स्कूलों के पास विदेशी शिक्षक हैं, या फिर मॉडर्न स्कूल, डीपीएस समेत अन्य स्कूलों के शिक्षक फिनलैंड से ट्रेनिंग लेकर आए हैं। जबकि इस स्कूलों का रिजल्ट दिल्ली सरकार के स्कूलों से अच्छा है।